(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) मुद्रास्फीति की दर जो अगस्त, 1991 के चौथे सप्ताह में 16.7 प्रतिशत के शीर्ष पर पहुंच गई थी, वह गिरकर 7 मार्च, 1992 को समाप्त सप्ताह में 12.6 रह गई थी। सरकार का निश्चय मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का है, इसलिए 1991-92 के दौरान मुद्रास्फीति की दर और अधिक कम हो जाने की आशा है। बृहत्-आर्थिक स्थिरीकरण की प्रक्रिया और आर्थिक सुधार जो वर्तमान वर्ष में आरंभ किए गए हैं, और 1992-93 के बजट प्रस्तावों में जिन्हें सुदृढ़ बनाया गया है, उनसे देश में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता लगभग सामान्य होने और उत्पादन में तीव्र वृद्धि लाने में सहायता मिलेगी जिससे मुद्रास्फीतिकारी दबाव कम हो जाएंगे।

विदेशी कंपनियों द्वारा बाहर भेजी गई विदेशी मुद्रा

4598. **डा० जिनेन्द्र कुमार जैन :**
श्री रणजीत सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले कुछ वर्षों में देश में विदेशी मुद्रा का बहिर्गमन निरन्तर बढ़ता जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1988-89, 1989-90 और 1990-91 के दौरान विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत आने वाली कंपनियों ने कितनी विदेशी मुद्रा देश से बाहर भेजी तथा यह धनराशि किन-किन मदों के नाम पर बाहर भेजी गई;

(ग) इन कंपनियों द्वारा उपरोक्त प्रत्येक वर्ष के दौरान देश के उद्योगों में कितनी विदेशी मुद्रा और भारतीय पूंजी निवेश की गई;

(घ) क्या यह भी सच है कि इन कंपनियों के लाभांश भारतीय कंपनियों से अधिक थे; और

(ङ) यदि हां, तो वर्ष 1990-91 में इन कंपनियों के विदेशी पूंजी निवेश के मुकाबले इनका लाभांश कितने प्रतिशत था?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर): (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कृषि क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋणों में वृद्धि

4599. **डा० जिनेन्द्र कुमार जैन :**
श्री राम जेठमलानी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि औसत उत्पादन दर में वृद्धि करने, नई तकनीकों और उपायों का प्रयोग करने तथा बीजों, उर्वरकों इत्यादि के अधिक मूल्यों के कारण भी कृषि क्षेत्र में अधिक पूंजी निवेश किये जाने की आवश्यकता है,

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा प्रति वर्ष मंजूर किए गए कुल ऋण में से कृषि क्षेत्र को औसतन कितने प्रतिशत ऋण दिया गया है; और

(ग) क्या सरकार ने इस प्रतिशतता को बढ़ाने के लिए कोई निर्णय लिया है; और यदि हां, तो कृषि क्षेत्र को ऋण प्रदान करने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) :(क) से (ग) वाणिज्यिक बैंकों के प्राथमिकता क्षेत्र ऋणों के मुख्य घटकों में कृषि भी एक घटक है कृषि ऋण को बढ़ाने पर जोर देने के लिए बैंकों से कहा गया था कि वे यह सुनिश्चित करें कि प्रत्यक्ष कृषि अग्रिमों का स्तर मार्च, 1985 के अन्त तक 15% और मार्च, 1987 तक 16% हो जाए। इन मानदण्डों की पुनः समीक्षा की गई और बैंकों से कहा गया था कि कृषि क्षेत्र को दिए जाने वाले प्रत्यक्ष वित्त को बढ़ाएं ताकि यह मार्च, 1989 तक उनके कुल ऋणों का 17% [illegible] मार्च, 1990 तक 18% हो जाए। इन लक्ष्यों की तुलना में कृषि (संबद्ध कार्यकलापों सहित) को प्रत्यक्ष वित्त देने में सरकारी क्षेत्र के बैंकों का कार्य निष्पादन निम्नलिखित था:—

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि
मार्च 1989	17%	16.4%
मार्च 1990	18%	16.5%
मार्च 1991	18%	15.1%